


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215347
CG-DL-E-11012020-215347

असाधारण

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2020/पौष 19, 1941

No. 111]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/ PAUSHA 19, 1941

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

का.आ. 121(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, भारत सरकार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर परिषद निम्नलिखित दो स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:

- (i) व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता
- (ii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता के लिए चेयरमैन स्पोर्ट्स अवार्ड।

और, इस स्कीम के अधीन पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को वजीफा तथा पुस्तक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के खेल कर्मियों को अपनी उत्कृष्टता दर्शाने के लिए चेयरमैन स्पोर्ट्स अवार्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राहियों कहा गया है) का प्रबंध किया गया है।

और, पूर्वोक्त स्कीम के तहत दिए गए लाभों में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्ष्यन परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात्:-

1. स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की वांछा करने वाले किसी व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी;

2. स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के हकदार ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, परंतु इस स्कीम के तहत लाभ उठाने का इच्छुक है, उसे उपरोक्त डीबीटी स्कीमों के लिए आवेदन करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टियों को आधार नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) जाना होगा;

3. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12, जो किसी भी व्यक्ति से आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखता है, के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, संबंधित राज्य के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय संबंधित राज्य के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा।

4. परन्तु व्यष्टि का आधार संख्यांक समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए प्रसुविधा दी जाएगी अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पर्ची; या

(ii) पैरा 5 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) पहचान प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज :-

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्रशीर्ष पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला 'पता कार्ड'; या (vii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

5. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदा देने के लिए, पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात्:-

(क) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने हेतु मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्ति सूचना दी जाएगी और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी। यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि आसपास के क्षेत्र जैसे ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय संबंधित राज्यों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करेगा और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर पूर्वोत्तर परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के संबंधित पदाधिकारियों अथवा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्टर कराएं।

6. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में प्रभावी होगी।

[सं.आईटी-12/2/2019-तकनीकी निदेशक (एनआईसी) का कार्यालय]

इन्दीवर पान्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 121(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables the beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

And whereas, the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region, Government of India is implementing the following two Schemes:

- i. Financial Support to the student of North Eastern Region pursuing professional courses.
- ii. Chairman's Sport Award for Excellence in National and International Sports Meet.

And whereas, financial assistance is provided by the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region, as Stipend and Book Grant (hereinafter referred to as benefits) among the students of NE States pursuing professional courses and also Chairman's Sports Award to the sports personnel of NE States for their excellence in National and International Sports meets (herein after referred to as the beneficiaries).

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18) of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. An individual desirous to availing benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication;

2. Any individual entitled to receive benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the Scheme, shall have to apply for Aadhaar enrolment before applying for the above DBT Schemes, in case he/she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment;

3. As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar, through the concerned State shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region through the concerned State may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming UIDAI Registrar itself.

4. Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely :-

(a) (i) if he/she has enrolled, his Aadhaar Enrolment slip ; or

(ii) a copy of his/her request made for Aadhaar Enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 5 and

(b) Following documents as identity proof:-

(i) 'Elector's photo identity card' issued by the Election Commission of India or (ii) 'Permanent Account Number Card' or (iii) 'Passport' or (iv) 'Driving License' issued by the Licensing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) or (v) 'Certificate of Identity' having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) 'Address card' having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) any other document as specified by the Ministry.

Provided, further that the above documents shall be checked by an officer designated by the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region for that purpose.

5. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the beneficiaries, the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region through the concerned State Government shall make all the required arrangements including the following:-

- (a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries, to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme with the advice to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas. In case they are not already enrolled, the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region through the concerned States are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials of the North Eastern Council, Ministry of Development of North Eastern Region or through the web portal provided for the purpose.

6. This notification shall come into effect in all North Eastern States from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. IT-12/2/2019-O/o Tech. Dir(NIC)]

INDEVAR PANDEY, Addl. Secy.